

आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
सोमवार 14.02.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :-

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया, इसे शक्ति के स्थान पर सेवा की भावना का प्रतीक बताया।
- बजट अधिवेशन का पहला चरण संपन्न। तीन सप्ताह के अवकाश के बाद दूसरे चरण के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक नौ मार्च से शुरू होगी।
- प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 20 अधिकारियों के तबादले।
- प्रदेश में "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" के तहत 630 शिविरों में 4 लाख 92 हजार लोगों ने हिस्सा लिया।

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल से दिल्ली में साउथ ब्लॉक के बजाय सेवा तीर्थ से कामकाज शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेवा तीर्थ के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन-एक और दो विकसित राष्ट्र की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। श्री मोदी ने सेवा तीर्थ में पहले दिन कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये। इनमें पीएम राहत योजना को मंजूरी, लखपति दीदियों के लक्ष्य को दोगुना करके छह करोड़ रुपए, कृषि बुनियादी ढांचा कोष को दोगुना करके दो लाख करोड़ रुपए और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण को दस हजार करोड़ रुपए की निधि की मंजूरी शामिल है। श्री मोदी ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और संकटग्रस्त नागरिकों से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री के रूप में कामकाज शुरू करने पर श्री मोदी के ये निर्णय सेवा की भावना को दर्शाते हैं तथा समाज के हर वर्ग को इसमें सम्मिलित करते हैं। प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ित डेढ़ लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकेंगे।

बजट स्थगित

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। यह 9 मार्च को बजट सत्र के दूसरे संस्करण के लिए फिर से बैठक होगी। बजट सत्र का पहला चरण पिछले महीने की 28 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दोनों सदनों के संयुक्त अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। दो चरणों में आयोजित बजट सत्र का दूसरा चरण इस वर्ष 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। एक रिपोर्ट-

नया रावल

15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रूद्रप्रयाग स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में 325वें नये रावल को नियुक्त किया जाएगा।

वर्तमान रावल 70 वर्षीय भीमाशंकर लिंग ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने 42 वर्षीय शिष्य शिवाचार्य शांतिलिंग, जिन्हें केदार लिंग के नाम से भी जाना जाता है, को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। वरिष्ठ पुजारी शिव शंकर लिंग ने रावल भीमाशंकर लिंग के हवाले से बताया कि शीतकाल में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं और इन दिनों रावल महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित अपने मठ में प्रवास कर रहे हैं। वहीं आयोजित एक कार्यक्रम में रावल ने लिखित रूप से अपने उत्तराधिकारी घोषित किया है।

तबादले

उत्तराखंड शासन ने भारतीय पुलिस सेवा-आईपीएस और प्रांतीय पुलिस सेवा पीपीएस के 20 अधिकारियों के स्थानांतरण और नई तैनाती के आदेश जारी किए। गृह सचिव शैलेश बगोली की ओर से जारी आदेश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार प्रमेन्द्र डोबाल को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून नियुक्त किया गया है, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून अजय सिंह को एसटीएफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ नवनीत सिंह को हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रदेश में हाल के दिनों में सामने आई आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर रुख अपनाते हुए पुलिस विभाग में प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक तबादले भी किए गए हैं। यह कदम पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्रिय, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को अपराध की रोकथाम के लिए केवल घटनाओं के बाद कार्रवाई ही नहीं, बल्कि पूर्व-निवारक रणनीति मजबूत करने के निर्देश दिए।

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार”

प्रदेश में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित समाधान का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। यह अभियान सरकार को सीधे जनता के द्वार तक ले जाकर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित कर रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित अभियान के तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों में आयोजित अब तक कुल 630 शिविरों में 4 लाख 92 हजार 395 लोगों ने हिस्सा लिया। जिनमें अब तक कुल 48 हजार 93 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 32 हजार 282 शिकायतों का निस्तारण मौके किया जा चुका है।

विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए अब तक 68 हजार 983 आवेदन प्राप्त हुए। जबकि विभिन्न सरकारी योजनाओं से 2 लाख 74 हजार 69 नागरिकों को लाभान्वित किया गया।

अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें अंतिम छोर तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि "सरकार जनता के द्वार पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और हर नागरिक को सम्मानपूर्वक न्याय मिलेगा।

आवास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन 2047 के तहत, उत्तराखंड सरकार राज्य में सुनियोजित, किफायती और नागरिक-अनुकूल आवासीय विकास को प्राथमिकता दे रही है। इसका लक्ष्य एक विकसित उत्तराखंड के लिए सतत विकास, बेहतर बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सुविधाओं के साथ नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना है। इसी क्रम में कल आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने प्राधिकरण की देहरादून आमवाला तरला आवासीय योजना का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण किए जाएं।

बैंकर्स समिति की 95वीं बैठक

देहरादून स्थित सचिवालय सभागार में सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 95वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30 सितम्बर 2025 तक की प्रगति की समीक्षा की गई।

सचिव ने जिन जिलों का क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो कम है, उन्हें तत्काल सुधार कर अनुपात बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही डिजिटल फ्रॉड एवं साइबर सुरक्षा के मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा तथा संबंधित एनफोर्समेंट एजेंसियों के समन्वय से लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाने एवं जागरूकता अभियान चलाये जाने पर जोर दिया।

साथ ही राज्य में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आरसेटी, एसएलआरएम, पीएमकेवीवाई एवं एनजीओ के माध्यम से जागरूकता शिविर आयोजित करने को कहा। जिन 9 जिलों में अभी तक शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण नहीं हुआ है, वहां 31 मार्च 2026 तक पूर्ण डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

निर्देश

नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिला विकास प्राधिकरण के अभियंताओं को आवासीय मानचित्रों को 15 दिनों में और गैर आवासीय मानचित्रों को 30 दिन के भीतर स्वीकृत करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने लम्बित मानचित्रों की एक समीक्षा बैठक में कहा कि मानचित्रों में आपत्ति की दशा में एक ही बार में आपत्ति को दर्शाते हुए संपूर्ण विवरण के साथ आवेदक को उपलब्ध कराकर उनका समय पर निराकरण किए जाने पर बल दिया।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून के राजपुर स्थित मॉल में हुए हत्याकांड की खबर सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता के साथ प्रकाशित की है। हिन्दुस्तान की सुर्खी— झारखंड के गैंगस्टर की दून में गोली मारकर हत्या।

ऑली में बर्फीले रोमांच का रंगारंग आगाज, चमोली जिले के औली में चार दिवसीय राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता और विंटर कॉर्निवल के शुभारंभ की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ लगाया है।

एक अन्य खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है—केंद्र सरकार ने 25 लाख टन गेहूं, पांच लाख टन चीनी के निर्यात की मंजूरी दी।